

Authorities get NHRC notice over manhole mishap

NEW DELHI, APRIL 9

Taking suo motu cognisance of the recent manhole mishap in Gurugram, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday said it had sought action from the authorities concerned in this matter.

On April 3, a two-year-old boy, died after falling into an uncovered manhole at Sihi village in Gurugram's Sector 37.

The NHRC has now issued notices to the Gurugram municipal commissioner and the police commissioner, seeking comprehensive reports in this regard within four weeks.

The commission stressed the gravity of the situation, considering it a potential violation of human rights. In its notices, the NHRC requested detailed information, including the current status of any FIR filed and whether any arrests had been made, in connection with the case. It also sought clarification on compensation. — PTI

Delhi Tribune 

बच्चे की मौत मामले का एनएचआरसी ने लिया संज्ञान

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: सेक्टर 37 थाना क्षेत्र के सीही गांव में दो अप्रैल की शाम ढक्कन न होने से खुले सीवर में गिरने से दो वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है।

एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेकर आयोग ने कहा कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री यदि सही है तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है, जो चिंता का विषय है। आयोग ने गुरुग्राम नगर निगम और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में दर्ज एफआइआर की स्थिति और क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में भी बताना होगा। आयोग ने कहा कि वह यह भी जानना चाहेगा

कि क्या बच्चे के स्वजन को कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं।

बता दें कि नेपाल के सुखैत जिले के रहने भगत सिंह सीही गांव में छह साल से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। इनकी गांव के बाहर ही चाय की दुकान है। बुधवार शाम साढ़े छह बजे इनका दो वर्षीय बेटा प्रदीप दुकान के पास ही खेल रहा था। खेलते-खेलते वह मेन लाइन सीवर के खुले होल के पास जा पहुंचा। ढक्कन न होने की वजह से वह इसमें गिर गया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने कहा था कि सीवर का ढक्कन खुला होने की वजह से यह हादसा हुआ। अगर ढक्कन बंद रहता तो बच्चा उसमें नहीं गिरता। उन्होंने जीएमडीए के अधिकारियों को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया था।



दो अप्रैल को गुरुग्राम के सीही गांव में रास्ते के बीच खुले इसी मैनहोल में गिरने से दो साल के बच्चे की मौत हो गई थी • जागरण

• गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को जारी किया नोटिस, चार सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

इस मामले में सेक्टर 37 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। जांच जारी है। इसमें जिस भी विभाग की लापरवाही सामने आएगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। फिलहाल एचएसवीपी को नोटिस जारी किया गया है। -सुरेंद्र सिंह, एसीपी, मानेसर



एनएचआरसी ने नोटिस भेजा

गुरुग्राम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गुरुग्राम के सेक्टर-37 में 12 फीट गहरे खुले मैनहोल में गिरने से दो वर्षीय बच्चे की मौत के मामले का स्वतः संज्ञान लिया। आयोग ने गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। गुरुग्राम के सेक्टर-37 इलाके में यह घटना तीन अप्रैल को हुई थी।

आयोग ने यह भी पूछा है कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं। इसके अलावा बच्चे के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं। बता दें कि बच्चा प्रदीप अपने पिता की चाय दुकान के पास खेल रहा था, तभी खुले मैनहोल में गिर गया था।

मैनहोल में गिरने से बच्चे की मौत पर एनएचआरसी ने दिया नोटिस

नगर निगम व पुलिस आयुक्त से **चार सप्ताह** में मांगी रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: सेक्टर 37 थाना क्षेत्र के सीही गांव में दो अप्रैल की शाम ढक्कन न होने से खुले सीवर में गिरने से दो वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लिया है।

एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेकर आयोग ने कहा कि समाचार रिपोर्ट की सामग्री यदि सही है तो यह मानव अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है, जो चिंता का विषय है। आयोग ने गुरुग्राम नगर निगम और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में दर्ज एफआइआर की स्थिति और क्या कोई गिरफ्तारी हुई है, इसके बारे में भी बताना होगा। आयोग ने कहा कि वह यह भी जानना चाहेगा कि क्या बच्चे के स्वजन को कोई मुआवजा दिया गया है या नहीं।

बता दें कि नेपाल के सुर्खेत जिले के रहने भगत सिंह सीही गांव में छह साल से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। इनकी गांव के बाहर ही चाय की दुकान है।

बुधवार शाम साढ़े छह बजे इनका दो वर्षीय बेटा प्रदीप दुकान के पास



दो अप्रैल को गुरुग्राम के सीही गांव में रास्ते के बीच खुले पड़े इसी सीवर मैनहोल में गिरने से दो साल के बच्चे की मौत हो गई थी • जागरण



इस मामले में सेक्टर 37 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। जांच जारी है। इसमें जिस भी विभाग की लापरवाही सामने आएगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। फिलहाल एचएसवीपी को नोटिस जारी किया गया है।

-सुरेंद्र सिंह, एसीपी, मानेसर

ही खेल रहा था। खेलते-खेलते वह मेन लाइन सीवर के खुले होल के पास जा पहुंचा। ढक्कन न होने की वजह से वह इसमें गिर गया था। इससे उसकी मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने कहा था कि सीवर का

ढक्कन खुला होने की वजह से यह हादसा हुआ। अगर ढक्कन बंद रहता तो बच्चा उसमें नहीं गिरता। उन्होंने जीएमडीए के अधिकारियों को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया था।

मैनहोल में गिरकर बच्चे की मौत पर एनएचआरसी ने भेजा नोटिस

गुरुग्राम, 9 अप्रैल (हप्र)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने तीन अप्रैल को गुरुग्राम के सेक्टर-37 में 12 फीट गहरे खुले मैनहोल में गिरने से दो वर्षीय बच्चे की मौत के मामले का

स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। नोटिस में आयोग ने पूछा है कि इस हादसे के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई। आयोग ने पूछा है कि अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं। इसके अलावा क्या बच्चे के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है। बता दें कि बच्चा प्रदीप अपने पिता की चाय दुकान के पास खेल रहा था, तभी खुले मैनहोल में गिर गया था। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एनएचआरसी ने पुलिस आयुक्त से जांच रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मैनहोल में गिरने से दो वर्षीय बच्चे की मौत का लिया संज्ञान

संवाद न्यूज एजेंसी

गुरुग्राम। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने सात दिन पहले मैनहोल में गिरने से दो साल के मासूम प्रदीप की मौत के मामले का खुद संज्ञान लिया है।

उसके बाद आयोग की ओर से नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को पत्र जारी कर अब तक



प्रदीप। फाइल फोटो

जांच रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि तीन अप्रैल को गुरुग्राम के सेक्टर

37 में 12 फीट गहरे खुले मैनहोल में गिरने से दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी।

कथित तौर पर बच्चा खुले मैनहोल के पास खेल रहा था। आयोग को समाचार पत्रों की रिपोर्ट से इसकी जानकारी मिली थी। जिसमें मामला गंभीर होने पर उसने खुद संज्ञान लिया है। रिपोर्ट में दर्ज एफआईआर की स्थिति और क्या

कोई गिरफ्तारी हुई है, शामिल होनी चाहिए। आयोग यह भी जानना चाहेगा कि क्या मृतक के परिजनों को कोई मुआवजा दिया गया है। 5 अप्रैल को आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को डेढ़ घंटे बाद मैनहोल से बाहर निकाला गया तथा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

Toddler's death: NHRC notice to Gurugram authorities

New Delhi: The National Human Rights Commission Tuesday said it has taken suo motu cognisance of a report of the death of a two-year-old boy who fell into an uncovered manhole in Gurugram and sought action from authorities concerned.

The incident occurred in Sihi village in Gurugram Sector 37 on April 3. The child, Pradeep Kumar, was playing near the tea stall of his father Bhagat Kumar when he fell into the manhole.

Taking cognisance of the report, the NHRC has issued notices

to the Gurugram municipal commissioner and the police commissioner, seeking comprehensive reports within four weeks.

The commission also sought clarification on whether any compensation has been provided to the family of the deceased. **PTI**

बच्चे की मैनहोल में गिरने से मौत पर हरियाणा सरकार को नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 9 अप्रैल।

खुले मैनहोल में गिरने से हुई दो साल के बच्चे की मौत की घटना को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया है। आयोग ने इस मामले में गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया है।

उनसे चार हफ्ते के भीतर घटना के बारे में विस्तृत जवाब मांगा है। हरियाणा सरकार को बताना होगा कि इस घटना की पुलिस में दर्ज प्राथमिकी की क्या स्थिति है। किसी को गिरफ्तार किया गया है या

मानवाधिकार आयोग ने
गुरुग्राम पुलिस आयुक्त
और नगर आयुक्त से
चार हफ्ते के भीतर
विस्तृत जवाब मांगा है।

नहीं। बच्चे के परिवारजनों को कोई आर्थिक सहायता दी गई है या नहीं। दुर्घटना की मीडिया में आई खबर का खुद संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है। दुर्घटना तीन अप्रैल को हुई

थी जिसकी खबर पांच अप्रैल को छपी। यह बच्चा खुले और गहरे मैनहोल के पास खेल रहा था और मेन हाल पर ढक्कन न होने के कारण उसमें गिर गया, जिसे डेढ़ घंटे बाद निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया तो डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

आयोग ने कहा है कि अगर खबर के तथ्य वाकई सही हैं तो यह मानवाधिकार हनन का एक गंभीर मामला है।

Systemic changes a must to curb fake encounters



SANKAR SEN
EX-DIRECTOR, NATIONAL
POLICE ACADEMY

ENCOUNTER specialists continue to pose grave problems for the police administration and operations. Recently, a notorious encounter specialist of the Mumbai Police, Pradeep Sharma, was sentenced to life imprisonment by the Bombay High Court in a 2006 case. The court also awarded a life sentence to 12 other cops, who were involved in the same case. This is exemplary punishment for trigger-happy police officers indulging in brazen illegalities.

However, the popular impression that fake encounters are the handiwork of errant cops is misleading. The hard fact to be acknowledged is that such encounters are the symptoms of a systemic malaise. At times, these encounters are staged by police officers because of the pressure exerted by their political masters and departmental bosses to show quick results by means fair or foul. The public, by and large, does not mind if cops take the law into their own hands and

become executioners in the case of dreaded criminals.

The police dilemma is compounded by the slow-moving criminal justice system. As trials drag on indefinitely in the courts, witnesses are easily gained over or turn hostile. Hence, the police face tremendous pressure to adopt extrajudicial methods and shortcuts. Some civil libertarians presume that extrajudicial killings stem from the 'bloodthirstiness' of the police officials. This is not always the case. The police are encouraged to do the dirty work because the criminal justice system is not functioning properly, and overhauling the system is an arduous and time-consuming job.

But the fact to be constantly borne in mind is that encounters are counterproductive and encourage contempt for the law within the police. Breaking the law in the name of law enforcement is unacceptable in a democratic society governed by the rule of law. It is unacceptable because it is arbitrary as a process and random in effect.

In its report, the National Police Commission strongly condemned false encounters as a remedy. The need of the hour is to strengthen the law and legal processes. Unfortunately, some senior police officers, instead of resisting pressure from their political masters, bend over backwards to please them. As the DIG in charge of the Crime Investigation Department



NOTORIOUS: Pradeep Sharma, an encounter specialist of the Mumbai Police, was recently sentenced to life imprisonment by the Bombay High Court in a 2006 case. PTI

(CID) of the Odisha Police, I was berated by then Chief Minister for not knowing all the tricks of the 'police tradecraft'.

Admittedly, in every police department, there are violence-prone officers who frequently indulge in a disproportionate use of force. In the US, the Christopher Commission, which looked into the misuse of force by the police after the Rodney King incident (1991) in Los Angeles, could pinpoint a few officers who were frequently crossing a red line. There should be no hesitation on the part of the

There are many in the police force who mistakenly believe that the end justifies the means.

police leaders to discipline and, if necessary, weed out the black sheep.

Thus, for dealing with the menace of fake encounters, systemic changes are called for. The National Human Rights Commission (NHRC), on receiving complaints of false encounters from the Andhra Pradesh civil liberties committee, held a public hearing in Hyderabad and recorded evidence. The NHRC Chairman, in a letter to the Chief Ministers, asked them to issue directions to all police stations through the Directors General of Police

on procedures to be followed where deaths had occurred in encounters with the police. The commission was of the view that the right to private defence should not be manipulated to justify fake encounters.

The procedure outlined by the NHRC laid down that in the case of an encounter in which the police were involved, immediate steps should be taken to investigate the facts and circumstances leading to the incident and ascertain how the offence was committed and by whom. Moreover, if officers belonging to the same police station are members of the encounter party, it would be appropriate that other police agencies, preferably the state CID, should take over the investigation of such cases. Unfortunately, these salutary instructions of the NHRC remain just on paper and are highlighted only in their breach. It is not known if the NHRC has taken firm and tangible measures to ensure that its mandatory instructions are acted upon.

In the Indian police, peer group supervision is also conspicuously missing, though it can be a powerful tool for ensuring accountability and all-round good policing. In Japan, police officers work in pairs with the understanding that one is responsible for the work and conduct of the other. Policemen work in groups in India also, but the ethos is

against the assumption of mutual responsibility. Peer supervision is closer and better informed than supervision by senior officers, but, unfortunately, it has remained a neglected aspect of internal regulation.

Violating the rule of law in the name of law enforcement is not desirable even from the limited point of view of the police. There are instances where criminals have used the police to bump off their rivals in intra-gang warfare. A research study by a former DGP of Maharashtra has shown how the Mumbai Police used to help one group of criminals eliminate their rivals in fake encounters.

There are many in the police force who mistakenly believe that the end justifies the means. However, the adoption of impermissible means ultimately vitiates the end. Further, violating the rule of law has the effect of 'scapegoating' the police. Police officers, particularly the top brass, have to constantly remember that when the police take recourse to extra-legal methods to make up for the deficiencies of law and legal procedures, they are trying to remedy inadequacies which they did not create. American scholar David Bayley has aptly said: "Illegality in the service of public safety makes policing a furtive and anxious activity and undermines the pride, which is the basis of job satisfaction."

Systemic changes a must to curb fake encounters



SANKAR SEN
EX-DIRECTOR, NATIONAL
POLICE ACADEMY

ENCOUNTER specialists continue to pose grave problems for the police administration and operations. Recently, a notorious encounter specialist of the Mumbai Police, Pradeep Sharma, was sentenced to life imprisonment by the Bombay High Court in a 2006 case. The court also awarded a life sentence to 12 other cops, who were involved in the same case. This is exemplary punishment for trigger-happy police officers indulging in brazen illegalities.

However, the popular impression that fake encounters are the handiwork of errant cops is misleading. The hard fact to be acknowledged is that such encounters are the symptoms of a systemic malaise. At times, these encounters are staged by police officers because of the pressure exerted by their political masters and departmental bosses to show quick results by means fair or foul. The public, by and large, does not mind if cops take the law into their own hands and

become executioners in the case of dreaded criminals.

The police dilemma is compounded by the slow-moving criminal justice system. As trials drag on indefinitely in the courts, witnesses are easily gained over or turn hostile. Hence, the police face tremendous pressure to adopt extrajudicial methods and shortcuts. Some civil libertarians presume that extrajudicial killings stem from the 'bloodthirstiness' of the police officials. This is not always the case. The police are encouraged to do the dirty work because the criminal justice system is not functioning properly, and overhauling the system is an arduous and time-consuming job.

But the fact to be constantly borne in mind is that encounters are counterproductive and encourage contempt for the law within the police. Breaking the law in the name of law enforcement is unacceptable in a democratic society governed by the rule of law. It is unacceptable because it is arbitrary as a process and random in effect.

In its report, the National Police Commission strongly condemned false encounters as a remedy. The need of the hour is to strengthen the law and legal processes. Unfortunately, some senior police officers, instead of resisting pressure from their political masters, bend over backwards to please them. As the DIG in charge of the Crime Investigation Department



NOTORIOUS: Pradeep Sharma, an encounter specialist of the Mumbai Police, was recently sentenced to life imprisonment by the Bombay High Court in a 2006 case. PTI

(CID) of the Odisha Police, I was berated by then Chief Minister for not knowing all the tricks of the 'police tradecraft'.

Admittedly, in every police department, there are violence-prone officers who frequently indulge in a disproportionate use of force. In the US, the Christopher Commission, which looked into the misuse of force by the police after the Rodney King incident (1991) in Los Angeles, could pinpoint a few officers who were frequently crossing a red line. There should be no hesitation on the part of the

There are many in the police force who mistakenly believe that the end justifies the means.

police leaders to discipline and, if necessary, weed out the black sheep.

Thus, for dealing with the menace of fake encounters, systemic changes are called for. The National Human Rights Commission (NHRC), on receiving complaints of false encounters from the Andhra Pradesh civil liberties committee, held a public hearing in Hyderabad and recorded evidence. The NHRC Chairman, in a letter to the Chief Ministers, asked them to issue directions to all police stations through the Directors General of Police

on procedures to be followed where deaths had occurred in encounters with the police. The commission was of the view that the right to private defence should not be manipulated to justify fake encounters.

The procedure outlined by the NHRC laid down that in the case of an encounter in which the police were involved, immediate steps should be taken to investigate the facts and circumstances leading to the incident and ascertain how the offence was committed and by whom. Moreover, if officers belonging to the same police station are members of the encounter party, it would be appropriate that other police agencies, preferably the state CID, should take over the investigation of such cases. Unfortunately, these salutary instructions of the NHRC remain just on paper and are highlighted only in their breach. It is not known if the NHRC has taken firm and tangible measures to ensure that its mandatory instructions are acted upon.

In the Indian police, peer group supervision is also conspicuously missing, though it can be a powerful tool for ensuring accountability and all-round good policing. In Japan, police officers work in pairs with the understanding that one is responsible for the work and conduct of the other. Policemen work in groups in India also, but the ethos is

against the assumption of mutual responsibility. Peer supervision is closer and better informed than supervision by senior officers, but, unfortunately, it has remained a neglected aspect of internal regulation.

Violating the rule of law in the name of law enforcement is not desirable even from the limited point of view of the police. There are instances where criminals have used the police to bump off their rivals in intra-gang warfare. A research study by a former DGP of Maharashtra has shown how the Mumbai Police used to help one group of criminals eliminate their rivals in fake encounters.

There are many in the police force who mistakenly believe that the end justifies the means. However, the adoption of impermissible means ultimately vitiates the end. Further, violating the rule of law has the effect of 'scapegoating' the police. Police officers, particularly the top brass, have to constantly remember that when the police take recourse to extra-legal methods to make up for the deficiencies of law and legal procedures, they are trying to remedy inadequacies which they did not create. American scholar David Bayley has aptly said: "Illegality in the service of public safety makes policing a furtive and anxious activity and undermines the pride, which is the basis of job satisfaction."